



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 197-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022 (KARTIKA 16, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 नवम्बर, 2022

संख्या 8/38/2022-1कII.- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 86/ह०अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का०आ० 86/ह०अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 3 में, उप-पैरा (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(viii) नगर पालिकाओं तथा नगर परिषदों की आधिकारिता में आने वाले गांवों के लाल डोरा में स्थित आवासीय सम्पत्तियों पर 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक उन सम्पत्ति स्वामियों को अनुमत होंगी, जो सभी देय/बकाया सम्पत्ति कर को चुकाता है।”।

अरुण गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 7th November, 2022

No. 8/38/2022-1CII.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with Sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, namely :-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 3, for sub-para (viii), the following sub-para shall be substituted, namely :-

“(viii) A rebate of 50% on residential properties situated in Lal Dora of villages falling in the jurisdiction of Municipal Committees and Municipal Councils shall be allowed upto 31st October, 2024 to those property owners who clear all property tax dues/arrears.”.

ARUN GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.